नईदुनिया

बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन एक मिसाल

सरकारें बदलीं वो बने रहे, चतुराई से यूनुस-रहमान को साधा

जमात शहाबुद्दीन को हसीना का प्रतीक मानती है, उन्हें हटाने के लिए लगा रहीं जोर

ढाका

बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन एक अनोखी मिसाल बन गए हैं। शेख हसीना सरकार के भरोसेमंद चहेते रहे वे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए मजबूरी बन गए और अब तारिक रहमान की बीएनपी सरकार में चतुराई से टिके हुए हैं। उनकी कहानी बांग्लादेश की सियासत की गहराई और दांव-पेच को दर्शाती है, जिस पर वहां की जमात-ए-इस्लामी पार्टी विराम लगाना चाहती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन की गिनती 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में होती है। तब वे छात्र नेता के रूप में सक्रिय थे1 अपने जन्म स्थान पबना में स्वाधीन बांग्ला छात्र संघर्ष परिषद के संयोजक थे। शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें कृषक श्रमिक अवामी लीग का जिला संयुक्त सचिव बनाया था। मुजीब की हत्या के बाद उन्हें तीन साल जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहा होने पर उन्होंने राजनीति से कुछ समय के लिए किनारा कर लिया। वे वकील बने, जिला न्यायाधीश रहे और फिर एंटी-करप्शन कमीशन में कमिश्नर की भूमिका निभाई। अवामी लीग के पुराने कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की जांच भी की।

रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में वे अवामी लीग की सलाहकार परिषद के सदस्य बने। अप्रैल 2023 में शेख हसीना सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पद पर नामित किया। बिना विरोध के वे 22वें राष्ट्रपति बन गए। यह फैसला शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना की विशेष पसंद माना जाता है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे अनजान थे। शहाबुद्दीन हसीना सरकार के लिए आदर्श व्यक्ति थे। वफादार, अनुभवी और कम विवादास्पद। उनकी नियुक्ति ने हसीना सरकार को संवैधानिक स्तर पर मजबूती दी। वे हसीना के चहेते साबित हुए।

अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद हसीना भारत पलायन कर गईं। मुहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने। इस दौर में शहाबुद्दीन देश के एकमात्र संवैधानिक प्रमुख बन गए। कई प्रदर्शनकारियों ने उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन वे हटा नहीं सके। यूनुस सरकार के अंतिम दौर में दिसंबर 2025 में शहाबुद्दीन ने रायटर्स को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि वे फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव के बाद इस्तीफा दे देंगे। यूनुस सरकार में उन्हें अपमानित महसूस हुआ। यूनुस ने सात महीने तक उनसे मुलाकात नहीं की, उनका प्रेस विभाग छीन लिया और सितंबर में रातोंरात विदेशी दूतावासों से उनके फोटो हटा दिए गए। जब शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को गुस्सा सड़क पर फूटा था, तब उनके हर नजदीकी को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे वक्त में बांग्लादेश सेना प्रमुख वाकर-उज-जमान उनकी रक्षा में आगे आए और फिर दोनों के बीच संपर्क नियमित हो गया।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका-ईरान वार्ता: तीन अरब डालर के फंड पर बनी सहमति, कतर में हुई बैठक: कूटनीति से रास्ते खुलने की उम्मीद

दोहा। पिछले कुछ महीनों से जारी भीषण संघर्ष के बाद, अमेरिका और ईरान अब कूटनीति के रास्ते पर लौटते दिख रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लागू करने को लेकर अच्छी खासी प्रगति हुई है। बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा जोर अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए ईरान के 3 बिलियन डालर के फंड को जारी करने पर रहा, और अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका इस फंड को जारी करने पर सहमत हो गया है, हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। यह बातचीत अप्रत्यक्ष रूप से हुई, जिसमें अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल एक कमरे में आमने-सामने नहीं बैठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम किया। ईरान के आधिकारिक डिप्टी विदेश मंत्री काजेम गारीबाबादी ने इस अप्रत्यक्ष वार्ता की पुष्टि की है। बैठक के दौरान, समझौते के किसी भी उल्लंघन को तुरंत रिकार्ड और रिपोर्ट करने के लिए एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने पर भी सहमति बनी है।ईरान के 3 बिलियन डालर के फंड को चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर शुरुआती सहमति बनी है, लेकिन अमेरिका ने इस पर स्पष्ट शर्तें रखी हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ईरान को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, और भविष्य में भी धनराशि तभी जारी होगी, जब ईरान समझौता ज्ञापन में तय सभी शर्तों को पूरा करेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने बताया कि इस्लामाबाद समझौते को लेकर हुई इस वार्ता में काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकाफ और उनके दामाद जारेड कुशनर ने कतर के प्रधानमंत्री से मिलकर इस पूरी वार्ता की जमीन तैयार की थी।

नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटे, पेट्रोल 20 और डीजल 30 रुपये प्रति लीटर सस्ता

काठमांडू। नेपाल आयल निगम ने पेट्रोलियम पदार्थों के खुदरा मूल्य में भारी कटौती की है। निगम के अनुसार नई कीमतें बुधवार देर रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसके तहत पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 20 रुपये, डीजल और मिट्टी तेल में 30 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। वहीं, घरेलू हवाई ईंधन में 40 रुपये और अंतरराष्ट्रीय हवाई ईंधन के लिए काठमांडू में प्रति किलोलीटर 265 अमेरिकी डालर की कटौती की गई है। इसके अलावा खाना पकाने वाली गैस भी प्रति सिलेंडर 100 रुपये सस्ती कर दी गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय हवाई ईंधन के लिए पोखरा और भैरहवा में बिक्री मूल्य ब्रेक-ईवन पाइंट पर ही कायम रखा जाएगा। नई दरों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए 197 रुपये प्रति लीटर चुकाने होंगे, जबकि डीजल और मिट्टी तेल 195 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह 14.2 किलोग्राम एलपी गैस सिलेंडर की कीमत 2060 रुपये और 7.1 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 1030 रुपये तय की गई है।

अमेरिकी हेलीकाप्टर की आपातकाल लैंडिंग होते ही 1 चालक गायब

वाशिंगटन। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के एक एमएच-60एस सी हाक हेलीकाप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, जिसके बाद से उसके चालक दल का एक सदस्य लापता है। इस घटना ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों पर ध्यान आकर्षित किया है, खासकर ईरान के साथ जारी तनाव के बीच। अमेरिकी नौसेना के बयान के अनुसार, 1 जुलाई को सुबह 3:30 बजे, यूएसएस जार्ज एच.डब्ल्यू. बुश युद्धपोत पर तैनात इस हेलीकाप्टर के पायलटों को आपातकालीन स्थिति में अरब सागर के पानी में उतरना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही, लापता सदस्य की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू कर दिया गया है। हेलीकाप्टर में कुल चार क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से तीन को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें यूएसएस जार्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर वापस लाया गया है, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल, इस आपातकाल लैंडिंग की वजह साफ नहीं हो पाई है और नौसेना ने इसकी जांच शुरू कर दी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नौसेना ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह इमरजेंसी किसी दुश्मन की कार्रवाई की वजह से हुई थी।

धमाकों से दहला यूक्रेन, कीव में कई जगह लगी आग, दो लोगों की मौत

कीव (यूक्रेन)

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की देश में रूस के बड़े हमले की चेतावनी के कुछ घंटे बाद गुरुवार तड़के राजधानी कीव और अन्य जगहों पर जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों से पूरा देश दहल गया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, राजधानी कीव में कई जगह आग लग गई। धमाकों की चपेट में आए दो लोगों की जान चली गई। जेलेंस्की ने एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर देशवासियों को चेताया था कि रूस रात को बड़े हमले की योजना बना रहा है। द कीव इंडिपेंडेंट, कीव पोस्ट और अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात ज्यादा हलचल नहीं हुई। सवेरा होने से पहले कीव में कई धमाके हुए। कीव के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इससे रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा और उनमें आग लग गई। हमले में कम से कम दो व्यक्तियों की मौत हो गई। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि हमलों के बाद कम से कम 11 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्लिट्स्को ने कहा कि बचावकर्मी नौ मंजिला इमारत के मलबे वाली जगह पर पहुंचे और अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस सब स्टेशन पर हमले में मेडिकल कर्मचारी घायल हुए हैं।

कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको के अनुसार, इस हमले में दो लोग मारे गए और कम से कम 16 अन्य घायल हो गए। इस हमले में आवासीय इमारतें भी नष्ट हो गईं। मध्य कीव में एक होटल क्षतिग्रस्त हो गया और बहुमंजिला इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजे तक अधिकारियों ने कम से कम 28 स्थानों पर नुकसान दर्ज किया ।

यूक्रेन के कई क्षेत्रों में हवाई अलर्ट जारी किया गया। दक्षिणी शहर जापोरिजिया और निप्रोपेत्रोव्स्क ओब्लास्ट के पावलोहराड में विस्फोट होने की सूचना है। पूर्वोत्तर यूक्रेन के सूमी और खार्किव में भी धमाके हुए हैं। तकाचेंको ने कहा, आने वाले दिनों में और हमले होने की भी संभावना है। विस्फोट शुरू होने से कुछ ही समय पहले यूक्रेन की वायुसेना ने चेतावनी दी कि रूसी ड्रोन के समूह कीव और मायकोलाइव, कोनोटाप और खेरसोन सहित अन्य शहरों की ओर बढ़ रहे हैं।

तकाचेंको ने रात 12:45 बजे कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे की चेतावनी दी। वायुसेना ने भी लगभग आधे घंटे बाद ऐसी ही चेतावनी जारी की। ओपन-सोर्स मानिटरिंग चैनलों ने बताया कि रूस ने 10 बाम्बर विमान तैनात किए। रात करीब दो बजे जोरदार धमाकों से कीव और अन्य शहर दहल गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राजधानी पर हुए हमले में शहर भर की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया और आम नागरिक व बचावकर्मी घायल हुए।

कीव के व्यस्त केंद्रीय इलाके पर भारी नुकसान हुआ है। यहां रिहायशी इलाकों के साथ-साथ संग्रहालय और विश्वविद्यालय भी हैं। तकाचेंको ने बताया कि शेवचेंकिव्स्की जिले में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग तबाह हो गई। पेचेर्स्की जिले में हमलों के कारण रिहायशी इमारतों के पास दो जगहों पर आग लगने की भी सूचना मिली है। सोलोमियांस्की जिले में एक प्रशासनिक इमारत के पास आग लग गई। होलोसीव्स्की जिले में एक और बहुमंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई।

जेलेंस्की ने बुधवार दिन में लोगों से सावधान रहने और हवाई हमले के सायरन पर ध्यान देने की अपील की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने एक्स पर कहा, इसी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे से सायरन बजने शुरू हो गए। सायरन सुनकर लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए।

यूक्रेन ने पिछले महीने रूस के खिलाफ अभूतपूर्व ड्रोन अभियान शुरू किया है। इसमें लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के जरिए ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है।जेलेंस्की ने इसे मास्को को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने की एक अहम रणनीति बताया है। पिछले हफ्ते एक ही रात में रूस ने 12 क्षेत्रों में 660 ड्रोन को रोकने की सूचना दी। इससे पहले जून में कीव के बीचों-बीच हुए रूसी हमले में यूक्रेन के एक प्रमुख मठ परिसर यूनेस्को की सूची में शामिल कीव पेचेर्स्क लावरा में आग लग गई थी।

वेनेजुएला भूकंप त्रासदी, हताहतों की संख्या 2,295, संयुक्त राष्ट्र को आंकड़ा 10,000 पहुंचने की आशंका

काराकास (वेनेजुएला)

वेनेजुएला में दिन गुजरने के साथ-साथ भूकंप त्रासदी में हताहतों की बढ़ती संख्या डरावनी होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने तो यह आंकड़ा 10,000 तक पहुंचने की आशंका जताई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जार्ज रोड्रिगेज के अनुसार, वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। रोड्रिगेज ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि हजारों अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

स्काई न्यूज की रिपोर्ट में जार्ज रोड्रिगेज और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक जियानलुका रैम्पोला डेल टिंडारो के हवाले से यह जानकारी दी गई। वेनेजुएला में 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप के बाद भारत समेत दुनिया भर के प्रमुख देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। टिंडारों ने माना कि संयुक्त राष्ट्र ने 10,000 बाडी बैग मंगवाए हैं। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार, 43,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रोड्रिगेज के अनुसार, 15,866 लोग बेघर हो गए हैं। नासा के अनुमान के अनुसार, 59,000 इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस समय बचावकर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों और अन्य पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। एक अमेरिकी जनरल ने बताया कि राहत कार्यों में मदद के लिए वेनेजुएला, प्यूर्टो रिको और कुराकाओ में 1,700 अमेरिकी कर्मियों को तैनात किया गया है। सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भारी दबाव है। वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम ने 500,000 लोगों को आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए 5 करोड़ डालर मदद की अपील की है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार 24 जून के दोहरे भूकंप के बाद वेनेजुएला में करीब 782 आफ्टरशाक्स दर्ज किए गए। अभी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मलबे को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका है। त्रासदी यह भी है कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। लेकिन देश में आए दोहरे भूकंप की वजह से ईंधन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

7 साल के बच्चे का 117 किलो वजन, हार्ट अटैक से मौत

वाशिंगटन। अमेरिका के मिशिगन राज्य से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने माता-पिता की जिम्मेदारी और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 साल के कैस्पर ओब्रायन नाम के एक बच्चे की मौत हार्ट फेलियर से हो गई, और इसका सबसे बड़ा कारण उसका अत्यधिक वजन था, जो चौंकाने वाला 117 किलो (255 पाउंड) था। पुलिस जांच के अनुसार, माता-पिता ने बच्चे को इतना अधिक खिला-खिलाकर मोटा कर दिया कि उसकी जान चली गई। यह घटना बाल उपेक्षा और क्रूरता का एक वीभत्स उदाहरण बन गई है। पुलिस ने बच्चे के माता-पिता, डेमियन ओब्रायन (40) और जेसिका ओब्रायन (41) पर सेकंड डिग्री मर्डर, चाइल्ड एब्यूज (बाल उत्पीड़न) और टार्चर (यातना) जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को कभी भी डाक्टर के पास नहीं ले जाया गया, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। घर में गंदगी का माहौल था, जो परिवार की लापरवाही को और उजागर करता है।

पाकिस्तान ने दी धमकी कहा- सिंधु जल के लिए हो सकती है जंग

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को सीधी धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। आसिफ ने चेतावनी दी है कि यदि यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हुआ, तो ईश्वर न करे, पानी को लेकर युद्ध भी हो सकता है। उन्होंने भारत को इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नई दिल्ली पानी को विवाद का मुद्दा बनाने पर आमादा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत का यह फैसला उसकी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश है, और यह उस 1960 के समझौते का उल्लंघन है जो दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच कई पूर्ण युद्धों के बावजूद कभी बाधित नहीं हुआ था। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का यह फैसला अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए एक बर्बर आतंकी हमले के बाद आया था। इस हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में घूमने आए 26 निर्दोष नागरिकों की धर्म पूछ-पूछकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद, भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौते से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को स्थगित करने का फैसला किया। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। भारत ने तर्क दिया था कि पानी साझा करने के

अंतरराष्ट्रीय समझौते मूल रूप से सद्भावना, आपसी सहयोग और ईमानदारी से जुड़ने पर आधारित होते हैं। कोई भी देश भारतीय जमीन पर सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए भारतीय नदियों से बिना किसी रुकावट के, कानूनी रूप से सुरक्षित रणनीतिक फायदों की मांग नहीं कर सकता। भारत के इस कड़े रुख के बाद, समझौते में अनिवार्य हाइड्रोलाजिकल डेटा साझा करना, द्विपक्षीय आयोग की बैठकें और किसी भी विवाद की स्थिति में हेग में मध्यस्थता न्यायालय का सहयोग लेने जैसी शर्तें प्रभावित हुई हैं। खुफिया विभाग के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, भारत के बातचीत से इनकार करने से पाकिस्तान का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व बुरी तरह घबरा गया है। विशेषकर इसलिए क्योंकि भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के बहाव को भौतिक रूप से मोड़े या रोके बिना, वहां जाने वाले पानी पर लगाम लगा दी है। ऐसा करते हुए भारत ने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में गुहार लगाने की क्षमता को भी प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने अपनी धरती पर पल रहे आतंकी संगठनों व उनके ढांचे पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जो भारत की नाराजगी का मुख्य कारण है।

नेपाल के ललितपुर में चीन के नौ नागरिक हिरासत में

काठमांडू

नेपाल के इमिग्रेशन विभाग ने ललितपुर से 9 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। राजधानी के ललितपुर धोबीघाट स्थित एक घर में बड़ी संख्या में चीनी नागरिकों के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की सूचना के आधार पर अध्यागमन विभाग ने बुधवार देर रात निगरानी और तलाशी अभियान चलाया ।

इस दौरान उस घर से 3 और चोभार क्षेत्र से संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न अन्य 6 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। विभाग के अनुसार जांच के लिए 18 चीनी पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि धोबीघाट के चार मंजिला घर में 29 चीनी नागरिक रह रहे थे। विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 11 पुरुष और 11 महिलाएं समेत कुल 22 चीनी नागरिक मिले। इनमें 4 व्यावसायिक वीजा और 18 पर्यटक वीजा पर नेपाल आए थे।

हालांकि सभी के पास वैध वीजा था, लेकिन

22 में से केवल 18 लोगों ने ही पासपोर्ट प्रस्तुत किए। बाकी 4 ने बताया कि उनके पासपोर्ट वीजा संबंधी कार्य के लिए वकील के पास हैं। इसके बाद जांच के लिए 18 पासपोर्ट जब्त किए गए। इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल के अनुसार, यह घर ड्रैगन ब्रिज इंटरनेशनल नामक कंपनी ने किराये पर लिया था।

निरीक्षण के दौरान घर को हास्टल बताया गया, लेकिन वहां हास्टल संचालन से जुड़ा कोई आधिकारिक साइनबोर्ड, उद्योग पंजीकरण, स्थानीय निकाय में व्यापार पंजीकरण या अन्य कानूनी दस्तावेज नहीं मिले। जांच में यह भी पाया गया कि पुरुष और महिलाओं को एक ही आवास में रखा गया था। खुद को हास्टल संचालक बताने वाले कर्मा शेर्पा और मंजु लामा के पास वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों का कोई रिकार्ड या वास्तविक विवरण उपलब्ध नहीं था।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अधिकांश चीनी नागरिक पर्यटक वीजा पर नेपाल में रहकर चोभार स्थित ट्रेजर्स प्रालि और ड्रैगन ब्रिज इंटरनेशनल प्रालि से जुड़े कार्यों में लगे हुए थे। ढकाल ने कहा, वे वीजा के उद्देश्य के विपरीत गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। यह घर सुमन कार्की के स्वामित्व में है और ड्रैगन ब्रिज इंटरनेशनल प्रालि द्वारा लीज पर संचालित किया जा रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रदर्शनी केंद्र के रूप में संचालित ट्रेजर्स प्रालि के भवन में अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था पाई गई। वहां बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे, निजी सुरक्षा गार्ड और आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध देखा गया। निरीक्षण के दौरान करीब 18 चीनी नागरिक वहां कार्यरत पाए गए, जिनमें अधिकांश पर्यटक वीजा पर थे। कर्मचारियों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। पासपोर्ट और पहचान पत्र दिखाने से इनकार किया गया। कर्मचारियों को कंपनी के वास्तविक संचालक के बारे में भी जानकारी नहीं थी। भवन के भीतर फोटो और वीडियो लेने पर भी प्रतिबंध था। विभाग ने बताया कि भवन के विभिन्न कमरों में टूरिस्ट प्रोहिबिटेड लिखे स्टिकर लगे थे। साथ ही निजी संस्थान द्वारा उपयोग किए जा रहे पास कार्ड पर नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह भी इस्तेमाल किया गया था।